of India for filling up vacancies in the High Courts are kept in view at the time of processing proposals for the appointment of Judges in the High Courts.

(e) In order to consider the problem of arrears of cases in courts and find out ways and means to deal with it as expeditiously as possible, a meeting of the Chief Ministers and Chief Justices of the High Courts was held on 4th December, 1993 under the Chairmanship of prime Minister. The resolutions adopted in the Conference have been commended to all the State Governments/UT Administrations and High Courts for necessary action. The administaration of Justice has been made a Plan item with a view to remove infrastructural bottlenecks coming in the way of expeditious disposal of cases.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1456. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) प्रत्येक पद किस-किस तारीख से रिक्त हैं, और

(ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1994 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 70 स्थायी पदों में से 69 पदों पर न्यायाधीश आसीन थे और स्थायी न्यायाधीश का एक पद रिक्त था। यह पद 1-11-1993 से रिक्त है। इसके अतिरिक्त, अपर न्यायाधीशों के 7 पद अनुमोदित कर दिए गए हैं और उन्हें नियुक्ति के समय पर मंजूर किया जाएगा।

(ग) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए सम्बद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि विद्यमान रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है।

Implementation of transfer policy of Judges

1457. SHRI S. S. SURJEWALA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court Government have started implementing the transfer policy for judges of various High Courts; if so, the number and names of Judges together with the courts to which they were posted during the last three years ;

(b) whether the criteria is being uniformly followed in each case ; and

(c) what criteria was followed in the transfer of Justice S. S. Sodhi, the Judge of Haryana High Court to Allahabad High Court ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) Transfer of Judges from one High Court to another is made on the recommendation of the Chief Justice of India in terms of Article 222 of the Constitution of India.

The Government have accepted as a policy, recommendations of the Law Commission in its 80th Report that there should be a convention according to which 1/3rd of Judges in each High Court should be from any other State. The Government have decided that this may be implemented either by making initial appointments from outside or by effecting transfers. The particulars of puisne Judges who have been transferred from one High Court to another in 1991, 1992 and 1993 are given in the enclosed Statement (*See* below).

(c) Transfer of Shri Justice S. S. Sodhi from Punjab & Haryana High Court to Allahabad High Court was made on the recommendations of the Chief Justice of India in terms of Article 222 of the Constitution of India.

Statement

Particulars of Puisne Judges Transferred from one High Court to another during 1991, 1992 and 1993

Sl. No.	Name of the Judge	Transferred	
		From	To
	S/Shri		
	1991		
1	D.J.J. Raju	Kerala	Andhra Pradesh
2	M.P. Kenia	Bombay	Allahabad
3	P.D. Muttal	Bomby	Kerala
4	G.C. Pandey	Allahabad	Madhya Pradesh
5	K. Sukumaran	Kerala	Bombay
6	B.M. Lal	Madhya Pradesh	Allahabad
7	B.P. Singh	Karnataka	Patna
8	B.P. Saraf	Gauhati	Bombay
	1992		
	Nil		
	1993		
1	S. Sagir Ahmad	Allahabad	Jammu & Kashmir
2	R.P. Sethi	Jammu & Kashmir	Punjab & Haryana
3	G.T. Nanavati	Gujarat	Orissa

गुजरात में निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम

1458. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1992-93 के दौरान कानूनी सहायता कार्यक्रम के अधीन कितने लोगों को लाभ मिला है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के निर्धारित सिद्धांतों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सच है कि 1992-93 के दौरान, गुजरात के लिए इस कार्यक्रम के अधीन जारी की गई निधियों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात में विधिक सहायता कार्यक्रमों के अधीन 46,847 व्यक्तियों को फायदा प्राप्त हुआ है।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लागू करने से विधिक सहायता कार्यक्रम को कानूनी आधार मिलेगा। अधिनियम में आय की अधिकतम सीमा का उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों के समक्ष मामलों की दशा में प्रतिवर्ष, 6,000 रु० से बढ़ाकर 9,000 रु० या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, करने और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले की दशा में प्रतिवर्ष 9,000 रु० से बढ़ाकर 12,000 रु० या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय निधियों का आबंटन "राज्य आधार" पर नहीं किया जाता है। वर्ष